

भारत सरकार  
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं० 1253  
दिनांक 25 नवम्बर, 2019

प्रयुक्त खाद्य तेल का पुनः प्रसंस्करण

1253. डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता:

क्या पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

(क) क्या सरकार और तेल वपणन कंपनियां प्रयुक्त खाद्य तेल से निर्मित बायो डीजल की पूरी मात्रा की खरीद करेंगी ता क देश में जैव-ईंधन क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा सके तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस वषय में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) देश भर में इस हेतु चयनित शहरों की संख्या और इस योजना की शुरुआत/कार्यान्वयन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने एक प्रयुक्त खाद्य तेल के पुनः प्रसंस्करण संबंधी एक 'री-परपज यूज्ड कु कंग ऑयल' (आरयूसीओ) व एक फोन-ऐप्लीकेशन जारी किया है जिससे प्रयुक्त खाद्य तेल की मात्रा का संग्रहण किया जा सके और और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री  
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) और (ख) : प्रयुक्त खाद्य तेल (यूसीओ) से जैव डीजल के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तेल वपणन कंपनियों ने पूरे देश में 100 स्थलों पर यूसीओ से उत्पादित जैव डीजल की आपूर्ति हेतु दिनांक 10.08.2019 को रुच की अभ्यक्ति आमंत्रित की है। यूसीओ आधारित जैव डीजल का कारखाने तक का मूल्य तीन वर्षों तक के लिए निर्धारित किया गया है। पहले वर्ष के लिए 51 रुपए/लीटर का मूल्य निर्धारित किया गया है, दूसरे वर्ष के लिए 52.7 रुपए/लीटर तथा तीसरे वर्ष के लिए 54.5 रुपए/लीटर का मूल्य निर्धारित किया गया है। इस मूल्य के अलावा जीएसटी और परिवहन प्रभार देय होंगे। दिनांक 10.10.2019 को इसका वस्तु 200 स्थलों तक कर दिया गया। राज्यसंघ शासित प्रदेश-वार स्थलों की संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

(ग): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) ने बताया है क वश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर दिनांक 10.08.2019 को प्रयुक्त खाद्य तेल का पुनः प्रसंस्करण (आरयूसीओ) स्टीकर और फोन ऐप लॉन्च कर गए थे। आरयूसीओ अनुपालक खाद्य कारोबार प्रचालकों (एफबीओज) तथा खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों द्वारा जागरूकता लाने तथा मांग पैदा करने के उद्देश्य से स्टीकर उनके परिसरों के बाहर प्रदर्शन के लिए हैं। जैसा एफएसएसआई द्वारा बताया गया है, फोन ऐप का प्रचालन नहीं किया जा रहा है।

अनुलग्नक

राज्य/संघ शासित प्रदेश	स्थलों की संख्या
आंध्र प्रदेश	12
अरुणाचल प्रदेश	1
असम	2
बिहार	18
चंडीगढ़	1
छत्तीसगढ़	3
दिल्ली	8
गोवा	2
गुजरात	14
हरियाणा	4
हिमाचल प्रदेश	1
जम्मू और कश्मीर	2
झारखंड	3
कर्नाटक	9
केरल	6
मध्य प्रदेश	5
महाराष्ट्र	17
मणिपुर	1
मेघालय	1
मजोरम	1
नगालैंड	1
ओडिशा	5
पंजाब	5
राजस्थान	12
तमिलनाडु	11
तेलंगाना	1
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	35
उत्तराखंड	2
पश्चिम बंगाल	16
योग	<b>200</b>